race in the region. Government have unambiguously conveyed India's concern at the adverse impact of such sales on the environment for peace, security and stability in the region.

गहरे समुद्र में मछलियों का शिकार

***243. श्री रामदेव भंडारी:**
श्री सुन्दर सिंह भंडारी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 नवबर, 1995 के "नवभारत टाइम्स" (दिल्ली संस्करण) में "श्रम संगठन लड़ेंगे मछुआरों की लड़ाई" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) उक्त समाचार के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है तथा क्या सरकार गहरे समुद्र में मछलियों के शिकार के लिए संयुक्त उद्यमों को दिए गए लाइसेंस रद्द कर रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव): (क) जी हां।

(ख) मछुआरों द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के संदर्भ में सरकार ने नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति की समीक्षा के वास्ते सिफारिशें करने के लिए भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री पी० मुरारी की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति का गठन किया है। अभी तक जारी की गई मंजूरियां मौजूदा नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति के अनुसार दी गई थीं। इसलिए पुनरीक्षा समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद ही आगे कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

Visit of Maldives President to India

*244. SHRI GOVINDRAO ADIK: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether the Maldives President visited India in August 1995; and

(b) if so, the details of agreements signed between the two countries?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) The President of the Republic of Maldives did not visit India in August 1995. The President visited India at the invitation of our President in March 1994, and in May 1995 in connection with the 8th Summit of the SAARC. No agreements were signed between the two countries during these visits. In September 1995, one agreement was signed between Government of Maldives, Government of India and the Educational Consultants India Limited (EdCIL). Under this agreement, EdCIL will undertake placement in Indian institutions of Maldivian candidates for training in key sectors identified by the maldives in its human resource development plan; Government of India will provide scholarships under ITEC for the candidates to be trained under this agreement.

पुलिस हिरासत तथा न्यायिक हिरासत में हुई मौतें

***245. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में पुलिस हिरासत तथा न्यायिक हिरासत में वर्ष-वार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई:

(ख) इन मौतों के लिए कितने व्यक्तियों को जिम्मेदार पाया गया और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए;

(ग) इन मौतों के लिए जिम्मेदार पाए जाने पर कितने व्यक्तियों को दण्डित किया गया; और

(घ) भविष्य में हिरासत में मौतों को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): (क) वर्ष 1992, 1993, 1994 और 1995 (30.11.1995 तक) के दौरान पुलिस हिरासत और